वर्तमान में ग्रामीण विकास का बदलता हुआ परिदृश्य

** डॉ0 सीताराम चौधरी

'प्रवक्ता राजनीति विज्ञान विभाग,राजकीय महाविधालय चिमनपुरा,शाहपुरा,जयपुर कोषाध्यक्ष– भारतीय गांधीयन अध्ययन समिति,भारत

गाँव का अर्थ है परिवारों का ऐसा जुडाव, जहाँ सबकी भूमिका एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न होकर एक दूसरे की पूरक होती है। पूरा गाँव भी दूसरे गाँव से इसी भाव से जुड़ता है, जो जनपद बनता है, जनपदों से देश बनता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वंय कर लेती थी। दूसरे शब्दों में, गाँव अपना राजा स्वंय था अर्थात गाँव निरकुंश तथा आत्मशासित था।[1]

नियोजित आर्थिक विकास के कारण भारत के गाँव अब पुराने गाँव नही रहे। उनमें कुछ अच्छाइयाँ आई हैं। गावं अब द्वीप नहीं रह गये है, वे दूर–दूर तक संचार साधनों से तथा परिवहन साधनों से जुड गये हैं। गाँव में भूस्वामित्व में अब कोई बिचोलिया नहीं है।कृषि के विकास हेतु नये–नये साधन पहुँच गये हैं–बीज, सिचाई बाबत पानी, उर्वरक और कीटनाशक। स्वतंत्रता के बाद गाँव में एक नयी शक्ति पैदा हो गयी है–मतदान का अधिकार (टवजपदह त्पहीज)। इसके कारण राजनीतिक दलों तथा राजनीतिज्ञों का ध्यान अब तक उपेक्षित रहे गाँवों तथा अर्थव्यवस्था की ओर आकृष्ट हुआ है। अब ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाने लगी है। स्पष्टतः गत दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलते हुए परिदृश्य का अध्ययन अग्राकिंत बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है।[2]

सकारात्मक परिवर्तन .

- भूमि पर किसान का स्वामित्व –स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के परिणामस्वरुप भूमि पर किसान का स्वमित्व हो गया है। अब किसान अपनी जोत का स्वंय मालिक है। तथा मध्यस्थों की समाप्ति हो गयी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक–सामाजिक–राजनैतिक बदलाव आया है। कल का मूजारा (खेतिहर मजदूर) आज जमींदार की बराबरी करने लगा है।[3]
- ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता –स्वतंत्रता से पूर्व गाँव तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जमकर शोषण किया गया। इससे गाँव अत्यधिक पिछड़ गये लेकिन गाँवों में उदित राजनीतिक जागृति के कारण गाँव अधिक समय तक पिछड़ नहीं रह सकते थे। गत तीन दशकों में सरकार तथा राजनीतिक दलों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है। अतः अब हमारी योजनाओं में ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाने लगी है।[4]
- कृषि का व्यावसायिकरण –ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बदलते हुए परिदृश्य के कारण कृषि अब मात्र आजीविका का साधन (।`वनतबम व`िसपअमसपीववक) नहीं रह गयी है। अब कृषि को एक व्यवसाय माने जाने लगा है। कृषकों का एक वर्ग, कृषि के व्यावसायिकरण के कारण कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग करने लगा है।[5]
- तकनीकी परिवर्तन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक पैमाने पर तकनीकी परिवर्तन हुए है। अब किसान उन्नत किस्म के बीजों (भ्लट) उर्वरकों, कीटनाशकों, सिचाईं के साधनों तथा आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी परिर्वतनों ने हरित क्रांति को सफल बनाया है।

- खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता –देश अब खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। स्वतंत्रता के समय जहाँ हमें खाद्य पदार्थों का आयात करना पडता था वहाँ अब हम अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का निर्यात करने लगे हैं। स्वतंत्रता के समय जहाँ देश में खाद्यान्न उत्पादन मात्र 5 करोड़ टन वार्षिक था वह बढकर वर्तमान में वर्ष 2016–17 में 850.42 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान हैं
- संचार क्रांति – पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण भारत में आधुनिक संचार साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को दूरभाषा से जोडा जा रहा हैं तथा गाँवों में डाकघरों की संख्या में वृद्धि की गई हैं[6]।

वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में ग्रामीण भारत में आयी संचार–क्रांति ने ग्रामीण विकास के नये आयाम स्थापित किये है। मार्च 2004 में देश में ग्रामीण–संलग्नता का अनुपात मात्र 1.57: था जो मार्च 2008 में बढकर 9.5: तथा मार्च, 2009 में 15.1: तथा दिसम्बर, 2016 में यह बढकर 67.5: हो गया। ग्रामीण दूरभाष–संलग्नता में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवा एवं इंटरनेट सुविधा में तीव्र गति से विस्तार हो रहा हैं। वर्तमान मोदी सरकार तो फ्री वाइ–फाई देने की योजना बना रही है। जो

- आर्थिक संरचना का विकास –ग्रामीण क्षेत्र में, गत कुछ वर्षों में आर्थिक संरचना का बडे पैमाने पर विकास हुआ है। विद्युत, परिवहन, सिंचाईं आदि का द्रुत गति से विकास हुआ हैं जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है।
- सामाजिक सेवाओं का विकास – योजनाबद्ध विकास के द्वारा गाँवों में शिक्षा, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवास,जल आपूर्ति इत्यादि सामाजिक सेवाओं का तीव्र गति से विकास किया जा रहा हैं।[7]
- उपभोक्ता संस्कृति का विकास – ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ है जिसकी आय व उपभोग का स्तर शहरी मध्यम व उच्च मध्यम आय वर्ग के लोगों से कम नहीं है। इससे शहरों के समीप स्थित गाँवों में भी उपभोक्ता संस्कृति का विकास हुआ है। यही नहीं, वे गाँव जो परिवहन, संचार तथा प्रचार माध्यमों के द्वारा शहरों से जुड गये हैं, आधुनिक उपभोक्ता वस्तुओं व टिकाऊ सामान की माँग के बडे केन्द्र बनते जा रहे हैं। अतः उपभोक्ता व टिकाऊ वस्तुओं के निर्माताओं में इस ग्रामीण बाजार को अपने कब्जे में करने की होड लगी हुई है।
- जाति प्रथा की समाप्ति –ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के कारण गाँवों में यद्यपि जाति प्रथा पूर्णतः समाप्त तो नहीं हुई है लेकिन शहरीवाद के प्रभाव के कारण गाँवों में जाति–प्रथा धीरे–धीरे समाप्त हो रही है। छुआछूत का बोलबाला अब पहले जैसा नहीं रहा है। कुछ वर्षों तक अस्पृश्य समझे जाने वाले लोग भी अब गाँवों में मंदिरों व पूजा स्थलों में प्रवेश करने लगे है।[8]

ऋणात्मक परिर्वतन.–

यद्यपि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं लेकिन गत कुछ वर्षों में गाँवों में अनेक ऋणात्मक परिवर्तन भी आये हैं। गाँवों में विकास के साथ–साथ अनेक बुराईयों का उदय हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निम्नाकिंत परिर्वतन आये है–

- वृक्षों की कटाई –जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, हदबन्दी तथा चकबन्दी के कारण गाँवों में वृक्षों की बडे पैमाने पर कटाई की गई है। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- झगड़े तथा मुकदमेबाजी –ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार ने अनेक कानून बनाये है। इन कानूनों को सही ढ़ंग से लागू न किये जाने के कारण गाँवों के लोगों में परस्पर वैमनस्य तथा झगड़ा बढ़ा है। अतः दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों की बाढ आ गई है।
- भ्रष्टाचार – सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अनेक संस्थाओं व अभिकरणों की स्थापना की है। इन

संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों–ग्राम सेवकों, पंचायत अधिकारियों, तथा खण्ड विकास अधिकारियों ने गाँवों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

- ग्रामीण कौशल की समाप्ति – ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगर तथा विशिष्ट कौशल एवं हुनर वाले लोग धीरे–धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन व सहायता नहीं मिल रही है। अतः उनके समक्ष अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है।
- ग्रामीण संस्कृति में बदलाव –तीव्र ग्रामीण विकास के कारण ग्रामीण संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। जो गाँव बिजली–पानी सड़क एवं आधुनिक संचार साधनों से जुड़ गए हैं वहाँ शहरी सभ्यता एवं संस्कृति का व्यापक प्रभाव दिखाई देने लगा है। गाँवों में अब पहले जैसा प्रेमभाव व भाईचारा नहीं रहा हैं। लोग स्वार्थी बनते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली भी समाप्त होती जा रही हैं।[9]

'प्रवक्ता राजनीति विज्ञान विभाग,राजकीय महाविधालय

चिमनपुरा, शाहपुरा,जयपुर

(कोषाध्यक्ष– भारतीय गांधीयन अध्ययन समिति,भारत)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. अग्रवाल एण्ड यादवग्रामीण विकास सहकारिता– दि स्टुडेन्ट्स बुक कम्पनी जयपुर, 1998–99
2. Economic Survey 2011-2012, Appendix A-89.
3. आर्थिक समीक्षा 2011–12, पृ. 316
4. Economic Survey 2011-12, p-307.
5. योजना आयोग की रिपाट 2012–2013
6. जनगणना 2011
7. बी.एन.युगान्धर एवं नीला मुखर्जीस्टडीज इन विलेज इण्डिया : इश्यूज इन रुरल डवलपमेंट, पृष्ठ 1–185
8. शर्मा, डॉ.श्रीनाथ पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, आदित्य पब्लिशर्स (मध्य प्रदेश) 2000 पृष्ठ 184–185
9. Economic Survey 2015-15, p-107.